



1. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि नारी शक्ति को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
3. वर्ष दो हजार सत्ताईस के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित की जा रही हैं।
4. पर्यटन विभाग इंटर-टाइडल वॉक पर चार-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।



भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिडिल प्वाइंट स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने संबोधित किया। यह कॉन्फ्रेंस संसद में 'महिला आरक्षण विधेयक' के पारित नहीं होने के संबंध में रखा गया। केन्द्रीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दो हजार छब्बीस तक परिसीमन विधेयक पारित न करने का निर्णय लिया था, जिसे संसद में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। परिसीमन एक संवैधानिक दायित्व है जिसे लंबे समय से टाला गया है, जिससे प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हुआ है। इसका लक्ष्य केवल सीटें बढ़ाना नहीं, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका प्राकृतिक अधिकार है। यह, संविधान एक सौ इक्कतीसवां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक, और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर केंद्रित है। भाजपा सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उनका उचित हक देने के लिए प्रतिबद्ध है।



सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक चूक या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनना चाहिए। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क में

राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा केवल दो प्रतिशत है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में इनका हिस्सा लगभग तीस प्रतिशत है। न्यायालय ने कहा कि टाले जा सकने वाले खतरों के कारण एक भी जान जाना राज्य की विफलता दर्शाता है। न्यायालय ने किसी भी भारी या व्यावसायिक वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग के कैरिजवे या पक्के शोल्डर पर निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों या अधिकृत सड़क किनारे की सुविधाओं को छोड़कर कहीं भी अन्य स्थान पर ना रोकने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे के भीतर किसी भी नए ढाबे, भोजनालय या व्यावसायिक ढांचे के निर्माण या संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसका प्रवर्तन उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।



केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नागरिकों से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने और स्वस्थ यकृत तथा स्वस्थ भविष्य के लिए प्रतिदिन बेहतर विकल्प चुनने का आह्वान किया। विश्व यकृत दिवस के अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि स्वस्थ यकृत स्वस्थ जीवन की कुंजी है। उन्होंने नागरिकों को मानव शरीर को स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करने में यकृत यानी लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लीवर को स्वस्थ रखने में पौष्टिक भोजन, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने जैसी सरल आदतों का विशेष महत्व है।



वर्ष दो हजार सत्ताईस के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें आमंत्रित की जा रही हैं। इस संबंध में इच्छुक व्यक्ति सहायक सचिव के कार्यालय के माध्यम से तीन जुलाई तक सिफारिश भेज सकते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों या सेवा के लिए दिए जाते हैं। सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। नामांकन केवल गृह मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल www.padmaawards.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन में व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्धि का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। नामांकन की अंतिम तिथि इक्कतीस जुलाई है।



केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा के तहत कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि मनरेगा के कार्य जमीनी स्तर पर बिना किसी बाधा के निरंतर चलते रहें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को समय पर काम उपलब्ध कराना और उनकी मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी क्रम में, श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी अनुरोध किया कि कार्यस्थलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए, जॉब कार्ड से वंचित ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड जारी किए जाएं, तथा इच्छुक परिवारों को शीघ्र रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि कोई भी इच्छुक परिवार रोजगार से वंचित न रहे। उन्होंने जानकारी दी कि महात्मा गांधी नरेगा के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस की प्रथम किस्त के रूप में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मजदूरी भुगतान हेतु सत्रह हजार सात सौ चवालीस दशमलव एक नौ करोड़ रुपये की राशि जारी की जा रही है।



पर्यटन विभाग इंटर-टाइडल वॉक पर चार-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अंडमान निकोबार पर्यावरण टीम और दक्षिण फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पच्चीस, सत्ताईस और तीस अप्रैल को भी चलेगा। इसमें उन प्रशिक्षुओं का चयन किया गया है, जिन्होंने पहले विभाग द्वारा आयोजित टूर गाइड और इको टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों के गाइडिंग कौशल को बढ़ाना और इंटर-टाइडल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता लाना है।



निकोबार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रीम वर्ल्ड एंटरटेनर्स 'स्टार्स ऑफ निकोबार' कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम कल शाम साढ़े पांच बजे मरीना पार्क में आयोजित किया जाएगा।



विज्ञान केन्द्र की ओर से कल से स्कूली और कॉलेज के छात्रों के लिए 'अंतरिक्ष संचार के व्यावहारिक पहलुओं' पर तीन-दिवसीय 'हैंड्स-ऑन' कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह कल सुबह साढ़े नौ बजे विज्ञान केन्द्र के सभागार में आयोजित किया जाएगा। बंगलुरु स्थित 'अकादमी फॉर एप्लाइड स्पेस कम्युनिकेशन' के सहयोग से यह कार्यशाला बाईस अप्रैल तक चलेगा।

